RAJYA SABHA

Monday, the 24th February, 2003/5 *Phalguna,* 1924 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Foreign Investment in Print Media

*81. SHRI K. NATWAR SINGH:†
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have now settled the issue of foreign investment/participation in the print media;

(b) whether it is a fact that at present foreign news agencies are only allowed to distribute news within the country through an Indian news agency owned and managed by Indians;

(c) if so, whether his Ministry is considering a review of the existing policy for operation of foreign news agencies in the country; and

(d) if so, the decisions taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) Yes, Sir.

(b) The extent policy in force since 1956 requires that the foreign news agencies distribute news in this country only through the Indian news agencies.

(c) and (d) It is felt necessary to consult with media persons/industry connected with the news agencies in order to ascertain if the 1956 policy on news agencies needs a detailed review given the rapid technological/ other changes noticed in the meantime.

SHRI K. NATWAR SINGH: Sir, with regard to part (a), he says "Yes, Sir". Could the distinguished Minister kindly expand this laconic reply as to what is precisely being done?

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri K. Natwar Singh.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, as far as the FDI in print media is concerned, the Government has come with a concrete policy. It has three distinct components. The first is a 26 per cent cap on FDI in newsprint, with adequate safeguard on editorials and editors, and three-fourths being Indian directors. Then, there is the second component on publication of Indian edition of foreign magazines, scientific speciality and sports; and the third is about a 74 per cent FDI in publication of foreign magazine, speciality scientific. These are the three distinct components, as far as the FDI print policy is concerned.

SHRI K. NATWAR SINGH: What steps have been taken to implement this executive decision of the Government?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, we have already come up with distinct guidelines. The guidelines are in place with all the structure safeguards. We, till date, have received two proposals for publication of Indian editions of foreign magazines which have been permitted. And five proposals have come. As far as FDI in the newspaper is concerned, till date, we have no proposals.

श्री सभापति: डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी साहब, आप पूछिए। आप कई दिनों बाद आए हैं, आप कहां थे?

प्रो॰ रामगोपाल यादव: पूजा करवा रहे थे..... (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि लगातार अनुपस्थित रहने वाले सदस्य कम से कम हाऊस में ऐक्सप्लेनेशन तो दें कि वे आज तक कहां थे?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: That is hard work. They are not doing hard work like me. To get three questions, you must do hard work, but they are not doing it.

श्री सभापति: वैडिंग ऐनिवर्सरी भी मनाई है आपने।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Every where he is celebrating anniversary.

श्री सभापति: आपका नंबर आया है या नहीं?

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: He does it in five-star hotels where we do not like to go.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Chairman, Sir, there has been a big controversy for the past 40-50 years. They have broken the rule to allow the foreign people to invest in the print media. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, what he has achieved till now and what are the advantages. In spite of the controversy, so many newspapers wanting and some not wanting, the Government has taken a decision. So, I would like to know through you, Sir, what they have achieved till today, how much money they have received, what is the advantage they have received and what care they have taken to see that the foreign media do not dominate the Indian media.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, the hon. Member would very much like to know that we had the widest consultation possible, including the matter being referred to the Standing Committee. The Standing Committee gave its Reports. While taking a policy decision, we have sought to allay all the apprehensions and address all the concerns that the predominance of Indian sector must be there. All the adequate guidelines are there. But there was a great demand from the media sector itself to allow this FDI in the newspaper print. Five proposals are there, two have been allowed. As far as the newspaper part is concerned, they are not there. But I wish to assure the hon. Members that adequate safeguards are there to allay all the concerns which they have expressed in the detailed guidelines issued in this behalf.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Chairman, Sir, my question is: What advantage have they got by allowing this? He must give a reply. He has not given a reply. What advantage has the Government got by allowing this controversial policy?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी हाल ही में इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है और पूर्व मंत्री भी यहां मौजूद हैं। इसलिए इसकी पृष्ठभूमि मैं यहां रखना चाहूंगी क्योंकि वे लगातार इस बात को यहां इस सदन के पटल पर दोहराती रही हैं कि यह सामयिक नहीं है चूंकि अखबार कोई उद्योग नहीं है।

मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आपकी जो यह समझ है, उसके मुताबिक आज अखबार अचानक उद्योग में बदल गए। क्या इस बात को आप समझते हैं कि अखबार का हमारे देश की जनता के मानस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उसके राजनीतिक विश्वासों पर, उसकी संवेदनाओं पर तथा उसकी चेतना पर अखबार का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसा है तो आपने संसद की स्थायी

समिति के व्यूज को, उनके मंतव्य को नजरअंदाज करते हुए तमाम अखबारों के संगठनों के व्यूज को नजरअंदाज करते हुए यह जो निर्णय लिया है, यह ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप ऐडिक्वेट सेफगार्ड्ज ले चुके हैं। जबकि गृह मंत्रालय ने भी इस बात पर ऐतराज किया है कि आज की जो हमारे देश की परिस्थिति है उसमें यह अनुकूल नहीं है। अभी तक भी आप बता नहीं पाए दोनों पूरक प्रश्नों के उत्तर में कि अब तक आपको क्या फायदा हुआ है। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि विभिन्न दबाव ग्रुपों के प्रभाव में आकर आप जो टुकड़े-टुकड़े करके दूरगामी प्रभावों वाली नीति ले रहे हैं यह हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि दबाव ग्रुपों के दबाव में न आकर एक कम्प्रीहेंसिव मीडिया पॉलिसी बनाएंगे तब जाकर इन पर निर्णय लेंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद: देखिए, जहां तक आपके पहले प्रश्न का उत्तर है इस पूरी नीति के निर्धारण के समय हम लोगों ने व्यापक विमर्श किया है और न्यूज-पेपर्स से संबंधित हर क्षेत्र से विमर्श किया है। अगर आप हमारी गाइड-लाईस को देखेंगी जो समय की बचत के कारण मैं विस्तृत नहीं पढ़ना चाहता हूं, आपकी तमाम चिंताओं का उसमें समुचित उत्तर है। एक, 3-4 डायरेक्टर हिन्दुस्तानी होंगे, सारे एडिटोरियल कंटेंट हिन्दुस्तानी होंगे, केस-बाई-केस बेसिस पर हमारे पास प्रस्ताव आएगा तब उस पर हम विमर्श के बाद विचार करेंगे और जो हिन्दुस्तान की सिक्योरिटी के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी अनुशंसा की थी उसका भी इसमें विस्तृत समाधान किया गया है। जहां तक इससे फायदे की बात है जो आपने भी दोहराया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बदलती हुई दुनिया में पूंजी निवेश हो, हमारी शर्तों पर हो, हमारी चिंताओं के समाधान के अनुसार हो, यह आग्रह था और इसीलिए हमने 26 परसेंट कैप रखा है। हमें लगता है कि यह नीति हमारी तमाम चिंताओं और संवेदनाओं का सामयिक विचार करते हैं और आपकी जो आशंका है इस आशंका का समाधान इसमें है। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति महोदय, बिल्कुल जवाब नहीं आया, आशंकाएं बनी हुई हैं वैसी की वैसी।

श्रीमती सरोज दुबे: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि प्रिंट मीडिया में विनिवेश देश की सम्प्रभुता पर क्या खुला हमला नहीं है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां निर्देश देना शुरू कर देंगी कि समाचार पत्र में क्या जाए और क्या न जाए? क्या राष्ट्र हित में है क्या राष्ट्र हित में नहीं है, इन सारी बातों से उनका कोई सरोकार नहीं रहेगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि किस प्रकार से देश हित की खबरों पर आप नियंत्रण रखेंगे? किस प्रकार से आप अपनी भूमिका उसमें बनाए रखेंगे ताकि देश की सम्प्रभुता और राष्ट्र हित के प्रतिकूल उसमें कोई समाचार न जाने पाए? एक बात और है। जब भी कभी यहां विदेशों का पूंजी-निवेश होगा तो जब कभी पूंजी निवेश करने वाले देश के खिलाफ कोई बात आएगी वे उसको कभी नहीं छापेंगे चाहे वह हमारे राष्ट्र हित के अनुकूल ही क्यों न हो?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति जी, माननीय सदस्या इस बात को समझेंगी कि सरकार खबरों पर नियंत्रण नहीं रखती, नियंत्रण रखने का काम सम्पादकीय मंडल का है। इसलिए हमने इस बात की विशेष चिंता की है कि सम्पादकीय मंडल में भारतीय लोग हों। यह हमारी गाइड-लाईंस में है। सरोज जी, आज तो एक बटन पर, इंटरनेट पर पूरी दुनिया का समाचार हमारे सामने होता है। आज दुनिया बदल रही है।

श्रीमती सरोज दुबे: आम आदमी के पास इंटरनेट कहां है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: दुनिया बदल रही है। तो बदलती हुई दुनिया के अनुसार हम लोगों ने व्यापक विमर्श करके यह निर्णय लिया है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय हित हमारी राजनीतिक, सामाजिक चिंताओं का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है और आपकी जो आशंकाएं हैं वे आशंकाएं निर्मूल हैं, यह मैं कहना चाहता हूं।

Inland Water Transport System

*82. MISS MABEL REBELLO:†
SHRI SANTOSH BAGRODIA:

Will the Minister of SHIPPING be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal of introducing inland water transport system in all cities that have some river running through it;

(b) whether Government plans to offer inland water transport as an economical transport service to the people; and

(c) if so, by when such transportation system is likely to be introduced in all cities that have rivers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI DILIP KUMAR MANSUKHLAL GANDHI): (a) and (c) No, Sir. Do not arise.

(b) Yes, Sir. Government are committed to the development of inland water transport as an efficient, environment friendly and economical means of transport for cargo and passengers. With this end in view the Ganga from Haldia to Allahabad, the Brahmaputra from Dhubri to Sadiya and the West Coast canal from Kottapuram to Kollam along with Champakara and Udyogmandal canals have been declared as National Waterways.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Miss Mabel Rebello.